मेड इन इंडिया योजना से मिली नई पहचान

सरकार ने 3 वर्षों के लिए 995 करोड़ का प्रस्ताव रखा

नयी दिल्ली, 19 अगस्त.भारत सरकार ने मेड इन इंडिया लेबल योजना की शुरुआत की है, जो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को नई पहचान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस योजना का उद्देश्य देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करना और उपभोक्ताओं को उनके प्रति विश्वास दिलाना है.

सरकार ने इस पहल के लिए तीन वर्षों में 995 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है.कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई. इसी समय भारत ने आत्मनिर्भर बनने के अवसर को पहचाना और मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की. इससे पहले 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने की नींव रखी. अब मेड इन इंडिया लेबल इन्हीं पहलों को जोड़ने वाला सेतु है. यह एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना है, जिसके तहत उत्पादों पर एक लोगो और क्यूआर कोड लगाया जाएगा. क्यूआर कोड स्कैन करने पर उपभोक्ता को निर्माण स्थल, वैधता और उत्पाद से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त होगी. इस पहल का नेतृत्व डीपीआईआईटी कर रहा है, जबकि भारतीय गुणवत्ता परिषद और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इसके सलाहकार हैं.

सरकार का विज़न भारत को एक स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, जिसकी पहचान स्थिरता, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से होगी. योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. पायलट सेक्टर का चयन कर गुणवत्ता मानक तय किए जाएंगे.

उद्देश्य

- भारतीय उत्पादों को मूल के आधार पर पहचान दिलाना.
- घरेलू और वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया को सशक्त करना.
- उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करना.
- एमएसएमई, कृषि और अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर व्यापक लाभ पहुंचाना.

2030 तक भारत बनेगा हरित हाइड्रोजन हब

वैश्विक मांग का 10% हिस्सा पाने की तैयारी में भारत : नाइक

19 कंपनियों को 8.62 लाख टन उत्पादन क्षमता मिली

नयी दिल्ली, 19 अगस्त.नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को कहा कि भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.

देश की नजर वैश्विक मांग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने पर है.नाइक ने फिक्की हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि 19 कंपनियों को 8.62 लाख टन वार्षिक हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों ने अपनी हरित हाइड्रोजन नीतियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है और कई अन्य इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ये राज्य भूमि आवंटन को सुगम बना रहे हैं, जल उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और विशेष रूप से हाइड्रोजन केंद्र के विकास के माध्यम से नवोन्मेष को प्रोत्साहित कर रहे हैं.नाइक ने बताया कि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 से अधिक हरित हाइड्रोजन मानक और प्रोटोकॉल को अपनाया जा चुका है या उन पर काम जारी है.

उन्होंने कहा, 'हम भारत को न केवल एक प्रमुख उत्पादक, बल्कि हरित हाइड्रोजन निर्यात का एक वैश्विक केंद्र भी बनाना चाहते हैं. इसका लक्ष्य वैश्विक मांग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करना है.' कई कंपनियां लागत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार में भारत को एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक साझेदारियां कर रही हैं. वैश्विक बाजार के 2030 तक 10 करोड़ टन से अधिक होने की संभावना है.

स्कूट एयरलाइंस ने शुरू की नई उड़ानें

भारत से अब जापान-थाईलैंड की आसान यात्रा

दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक नई उड़ानें शुरू

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (वार्ता) सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट ने मंगलवार को थाईलैंड के चियांग राय और जापान के ओकिनावा तथा टोक्यो के लिये सिंगापुर से नयी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की.

कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये उड़ानें दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच एक-एक करके शुरू होंगी, जिससे साल के अंत और नये साल के मौके पर घूमने जाने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे. भारत से यात्री अमृतसर, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम्, तिरुचिरापल्ली और विशाखापत्तनम् से सिंगापुर के रास्ते तीनों गंतव्यों की बुकिंग करा सकते हैं.

थाईलैंड के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वतीय इलाका चियांग राय अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. वहां की आबादी में विभिन्न पहाड़ी जनजातियां शामिल हैं. स्कूट 01 जनवरी 2026 से एम्ब्रेयर ई190-ई2 विमान से चियांग राय के लिए उड़ान शुरू करेगी. सप्ताह में पाँच उड़ानें होंगी. जापान का उपोष्णकटिबंधीय स्वर्ग कहा जाने वाला ओकिनावा एक द्वीपसमूह है जो अपने प्राचीन समुद्र तटों, साफ पानी और अद्वितीय रयूकू संस्कृति के लिए जाना जाता है. सांस्कृतिक और प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से समृद्ध ओकिनावा और जापान की राजाधानी टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे के लिए भी स्कूट सेवाएं शुरू करेगी. ओकिनावा के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें 15 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी. एरलाइंस इस मार्ग पर एयरबस ए320 परिवार के विमान का परिचालन करेगी.

स्कूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस्ली थंग ने कहा, चियांग राय, ओकिनावा और टोक्यो (हनेडा) के लिए नयी उड़ानों के साथ एशिया में स्कूट के नेटवर्क का विस्तार करके हमे बेहद खुशी हो रही है . इससे हमारे ग्राहकों को यात्रा को और भी ज्यादा विकल्प मिलेंगे .

भारत में लॉन्च हुआ चैटजीपीटी गो प्लान

यूपीआई से आसान भुगतान की सुविधा

जीपीटी-5 आधारित, दस गुना अधिक मैसेज लिमिट

नई दिल्ली, 19 अगस्त. अमेरिकी तकनीकी दिग्गज ओपनएआई ने मंगलवार को भारतीय यूजर्स के लिए एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान, 'चैटजीपीटी गो' लॉन्च करने की घोषणा की. कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'चैटजीपीटी गो' जीएसटी सहित 399 रुपए प्रति माह की दर से उपलब्ध है, जिसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है.

इस नई योजना का उद्देश्य भारत में यूजर्स के लिए उन्नत एआई टूल्स को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है. 'चैटजीपीटी गो' की सभी सुविधाएं जीपीटी-5 द्वारा संचालित हैं, जहां यूजर्स भारतीय भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं. 'चैटजीपीटी गो' मुफ्त योजना की तुलना में जीपीटी-5 के साथ दस गुना अधिक मैसेज लिमिट प्रदान करता है.विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रतिदिन दस गुना अधिक इमेज जनरेशन प्रदान करता है. यूजर्स प्रतिदिन 10 गुना अधिक फाइल और इमेज अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, इसमें पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स के लिए दोगुनी मेमोरी भी है. यह नया ऑप्शन मौजूदा सब्सक्रिप्शन टायर के साथ उपलब्ध है, जिसमें 1,999 रुपए प्रति माह की दर से चैटजीपीटी प्लस भी शामिल है, जो पावर यूजर्स के लिए प्राथमिकता पहुंच, तेज प्रदर्शन और उच्च उपयोग सीमा प्रदान करता है.

टीसीएस ने मेक्सिको में खोला नया केंद्र

मुंबई, 19 अगस्त (वार्ता) देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस ने लातिन अमेरिका में नवाचार बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुये मंगलवार को मेक्सिको में नया एआई आधारित ऑपरेशन केंद्र खोलने की घोषणा की.

कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मेक्सिको सिटी स्थित नया कार्यालय मेक्सिको में उसका आठवां ऑपरेशन केंद्र है. कंपनी ने पिछले 22 साल में देश में 11 हजार कुशल एसोसिएट्स का कार्यबल तैयार किया है. नया केंद्र अगले दो साल में रोजगार के और अवसर पैदा करेगा. इस केंद्र पर एआई विशेषज्ञों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तैनाती की जायेगी.

भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी शुल्क असर सीमित : फिच

नयी दिल्ली, 19 अगस्त.फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी उच्च शुल्क का सीधा असर सीमित है लेकिन अभी प्रभावित नहीं हुए दवा जैसे क्षेत्र भी भविष्य में होने वाली घोषणाओं की चपेट में आ सकते हैं.

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के आयात पर सात अगस्त से 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगा दिया है. इसके अलावा रूसी तेल का आयात जारी रखने के दंडात्मक जुर्माने के तौर पर 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क भी लगेगा.

इस तरह भारत, अमेरिका में 50 प्रतिशत सीमा शुल्क के साथ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक शुल्क का बोझ उठा रहा है.फिच रेटिंग्स ने इस शुल्क के प्रभावों पर जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा शुल्क से भारतीय कंपनियों पर परोक्ष असर बढ़ने का भी जोखिम दिख रहा है. हालांकि, अमेरिका-भारत व्यापार समझौता हो जाने पर यह जोखिम कम हो जाएगा.

कपास आयात शुल्क खत्म

30 सितंबर तक कपड़ा क्षेत्र को मिलेगा सस्ता कच्चा माल

नयी दिल्ली, 19 अगस्त.सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार के लिए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है.कपास पर अब तक 11 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगता था.

वित्त मंत्रालय की 18 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, शुल्क छूट 19 अगस्त यानी आज से प्रभावी हो गई और 30 सितंबर तक लागू रहेगी.आयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है. घरेलू स्तर पर इस क्षेत्र को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत व्युत्क्रम कर संरचना का भी सामना करना पड़ रहा है.भारत के आयात शुल्क में राहत ऐसे समय में दी गई है, जब कपड़ा क्षेत्र सहित भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50 प्रतिशत की भारी शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है.

आईओसी-एयर इंडिया का समझौता

नयी दिल्ली.सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एयर इंडिया को पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह भारत में हरित और स्वच्छ विमानन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.आईओसी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी के अनुसार, कंपनी इस साल दिसंबर से अपनी पानीपत रिफाइनरी में इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल से पर्यावरण अनुकूल विमानन ईंधन का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है. इस संयंत्र से आईटीसी और हल्दीराम जैसी होटल और रेस्तरां से इस्तेमाल के बाद बचे अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके सालाना 35,000 टन हरित ईंधन का उत्पादन होने की उम्मीद है.

बैराबी-सैरांग रेल नेटवर्क से जुड़ा आइज़ोल

आइज़ोल,19 अगस्त. पूर्वोत्तर भारत का प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण राज्य मिज़ोरम पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ गया है. बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन के निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही राज्य की राजधानी आइज़ोल अब रेल मार्ग से भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ गई है.

लगभग 8071 करोड़ की लागत से बनी 51.38 किमी लंबी इस रेल परियोजना में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं. इसमें 114 मीटर ऊंचा पुल संख्या 196 देश की इंजीनियरिंग क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है. परियोजना का कार्य 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था और मई 2025 में सफल ट्रायल रन के साथ इसका निर्माण पूर्ण हुआ.

यह रेल मार्ग न केवल परिवहन को सुगम बनाएगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा. सुरंगों और संरचनाओं को मिजो संस्कृति दर्शाने वाले भित्तिचित्रों से सजाया गया है, जिससे यह रेलमार्ग सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी बनेगा. इससे जीवन यापन की लागत में कमी, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. रणनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है. सैरांग से म्यांमार सीमा तक 223 किमी नए रेल मार्ग का सर्वे भी स्वीकृत हो चुका है.

समाचार विशेष

नए नवेले जिलाध्यक्षों ने बढ़ाई राहुल की टेंशन

घमासान के बाद दिल्ली तलब हुए जिला अध्यक्ष

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है. नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही गुटीय कलह उजागर हो गई है. इस फैसले के बाद से बयानबाजी और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है. वहीं दूसरी ओर, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण के लिए 24 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नए जिलाध्यक्षों से बातचीत करेंगे .

कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत राज्य के 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इन जिला अध्यक्षों में विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं. इनमें कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाते रिश्तेदार भी हैं. इतना ही नहीं, कई जिला अध्यक्षों को एक बार फिर कमान सौंपी गई है. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी में नाराजगी बढ़ने लगी है और इन नियुक्तियों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. गुना का जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को बनाया गया है, इससे उनके समर्थकों में नाराजगी है. समर्थकों का कहना है कि प्रदेश स्तरीय नेता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. विरोध में उतरे कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का पुतला तक दहन किया. इसी तरह डिंडोरी से आदिवासी चेहरे ओंकार सिंह मरकाम को अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.

संभागीय प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा- o इसके अलावा, इंदौर में चिंटू चैकसे और विपिन वानखेड़े को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध हुआ है और संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने तो इस्तीफा तक दे दिया है. इतना ही नहीं, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष साक्षी डागा ने भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोला है. इसके अलावा, भोपाल के जिला अध्यक्ष पद के दावेदार प्रदीप उर्फ मोनू सक्सेना ने प्रवीण सक्सेना को फिर भोपाल का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जताई है और कांग्रेस नेताओं की भाजपा के साथ-गांठ का भी आरोप लगाया है.

24 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे संवाद

विरोध प्रदर्शनों के बीच गुना के जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने जब भोपाल में आकर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा था कि जिले के सबसे सक्षम और ताकतवर नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा और उन्होंने यह किया है, जिससे पार्टी को लाभ होगा. वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आगामी दिनों में जिला अध्यक्षों को दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे. बताया गया है कि राज्य में जिन जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है उन सभी को 24 अगस्त को दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाने वाला है. इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे.

पंजाब की पंथक राजनीति में बदलाव

चंडीगढ़. पंजाब की पंथक राजनीति में अहम बदलाव हुआ है. ज्ञानी हरप्रीत सिंह को शिरोमणि अकाली दल बागी गुट का नया प्रधान चुन लिया गया है. श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित की गई भर्ती कमेटी के चुनावी इजलास के दौरान श्री अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सर्वसम्मति से शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है.

ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष भाई अमरीक सिंह की बेटी बीबी सतवंत कौर को सर्वसम्मति से सिख काउंसिल की अध्यक्ष चुना गया है. डेलीगेट इजलास में संता सिंह की ओर से ज्ञानी हरप्रीत सिंह का नाम अध्यक्ष के रूप में पेश किया गया. उनके मुकाबले कोई भी और नाम पेश नहीं हुआ जिस कारण ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया. यह इजलास अमृतसर स्थित निहंग संगठन बुड्ढा दल के कार्यालय बुर्ज अकाली फुलासर में आयोजित किया जा रहा है. श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित की गई भर्ती कमेटी का दावा है कि 12 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए हैं. करीब 12,000 डेलिगेट्स बनाए हैं. वहीं, अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए करीब 500 डेलिगेट्स चुने हैं. चुनावी इजलास निहंग जत्थेबंदी बुड्ढा दल की छावनी बुर्ज अकाली फूला सिंह में हुआ.

विशेष | **राज्यसभा में शिबू सोरेन का स्थान किसे देगा झामुमो?**

रामदास सोरेन के बेटे सोमेश को मिलेगी उनकी जगह!

रांची. एक माह एक भीतर झारखंड ने दो बड़े नेताओं को खो दिया है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन के निधन से राज्य की राजनीति में बड़ा असर पड़ा है. आने वाले कुछ दिनों के भीतर सरकार और झामुमो को कई बड़े फैसले लेने होंगे. शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गयी है. वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से कैबिनेट में भी एक जगह खाली है.

सोमेश सोरेन का नाम लगभग तय- झामुमो सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को कैबिनेट में उनकी जगह मिल सकती है. मालूम हो स्व रामदास के तीन बेटे हैं. सोमेश अपने पिता रामदास सोरेन के समय से ही उनके साथ राजनीति में सक्रिय रहे हैं. विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता का काम देखते रहे हैं. हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसला लेना है. परिवार के लोगों के साथ सीएम लगातार संपर्क में हैं. रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना तय है. छह महीने के अंदर ही चुनाव कराये जाने की वैधानिक बाध्यता है. घाटशिला के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ है. यह सीट झामुमो की है. झामुमो रामदास सोरेन के परिवार के बीच ही इस सीट की बागडोर देगा. रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक सूत्रों की मानें, तो यह लगभग तय है.

राज्यसभा में एक सीट खाली- शिबू सोरेन का राज्यसभा में कार्यकाल 21 जून 2026 तक था. उनके निधन के बाद राज्यसभा में एक सीट खाली हो गयी है. राज्यसभा का चुनाव होता है, तो झामुमो के अंदर कई नेता रेस में होंगे. शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता की जगह पार्टी को नाम तय करने होंगे. झामुमो की कोशिश होगी कि ऐसे उम्मीदवार का चयन हो, जिससे एक पॉलिटिकल मैसेज भी जायें. पार्टी कैडर और शिबू सोरेन के नजदीक रहे लोगों को मौका मिल सकता है.

अब सीपी राधाकृष्णन का झारखंड कनेक्शन

रांची. यह गजब संयोग है कि राष्ट्रपति के बाद उप राष्ट्रपति का भी झारखंड कनेक्शन निकल आया है. उप राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा की ओर से घोषित एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे. वे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक राज्यपाल रहे थे और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के साथ ठीक ठाक संबंध रहा था. हालांकि उनके राज्यपाल रहते ही राजभवन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ था और उनको गिरफ्तार किया गया था. वे राजभवन से गिरफ्तार हुए थे. झारखंड के बाद राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना कर भेजा गया. उनका उप राष्ट्रपति होना तय माना जा रहा है.

मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रही हैं. उनके नाम सबसे लंबे समय तक झारखंड का राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है. वे 2015 से 2021 तक यानी छह साल तक राज्यपाल रही थीं.

नई पार्टी तैयार करने पर सहमति

विरोधी ग्रुप का आरोप है कि मौजूदा नेतृत्व विशेषकर सुखबीर बादल पार्टी को पंथक सिद्धांतों से भटका रहे हैं. यही कारण है कि अकाल तख्त साहिब ने भर्ती कमेटी का गठन किया और अकाली दल का संविधान के अनुसार पुनर्गठन कर नई पार्टी तैयार करने पर सहमति बनी. यदि विद्रोही गुट अपने एजेंडे में सफल रहा है, तो पार्टी के दो धड़े सुखबीर नेतृत्व और नया पंथक धड़ा अलग-अलग राह पर होंगे. इससे शिरोमणि अकाली दल की राजनीति खतरे में पड़ सकती है. इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा. ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बागी ग्रुप के अध्यक्ष बनने पर शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.